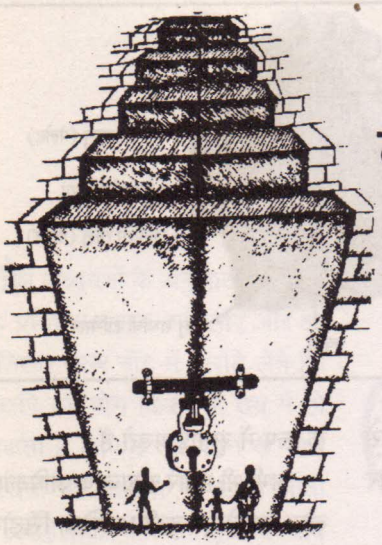

अनाज है भंडार में, लोग हैं भुखमरी की कगार पे

अमूल्य निधि व भाऊसाहेब आहेर

तीन वर्ष पूर्व बड़वानी के ज़िला बनने के साथ ही ऐसी आशा जगी थी कि ज़िले के सर्वाधिक पिछड़ेविकासखण्ड पिछड़ेपन से बाहर आ जाएंगे और लोगों को मूलभूत सेवाओं के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। परंतु लगातार पड़ रहे सूखे से बच्चों और बड़ों दोनों में कुपोषण तेज़ी से बढ़ रहा है।

मध्यप्रदेश के बड़वानी ज़िले के सूखाग्रस्त क्षेत्र में लोग गम्भीर कुपोषण से पीड़ित हैं। हालांकि पहले भी इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन पिछले तीन साल से लगातार पड़ रहे सूखे ने इस क्षेत्र में आम जनता के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को और भी बदतर बना दिया है।

यह स्थिति सिर्फ बड़वानी ज़िले की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और सम्पूर्ण देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की है। यह लेख बड़वानी ज़िले के पाटी व बड़वानी विकासखण्ड में कुपोषण पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। बड़वानी ज़िले के ये दोनों विकासखण्ड सर्वाधिक पिछड़े हुए माने जाते हैं। तीन वर्ष पूर्व बड़वानी के ज़िला बनने के साथ ही ऐसी आशा जगी थी कि ये विकासखण्ड पिछड़ेपन से बाहर आ जाएंगे और लोगों को मूलभूत सेवाओं के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। परंतु लगातार पड़ रहे सूखे से बच्चों और बड़ों दोनों में कुपोषण तेज़ी से बढ़ रहा है। जन स्वास्थ्य समिति द्वारा किए गए सर्वे के आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है।

जन स्वास्थ्य समिति पिछले दो सालों से ज़िले की स्वास्थ्य परिस्थिति में सुधार के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। सूखे के कारण लोगों के बिगड़ते स्वास्थ्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए समिति ने इस सर्वे का निर्णय लिया।

सर्वे की विधि

जन स्वास्थ्य समिति ने यह सर्वे तीन चरणों में किया :

1. स्वास्थ्य साथी (सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) महिलाओं द्वारा 5 साल से छोटे बच्चों व वयस्कों के कुपोषण की जांच की गई;

2. 1 से 5 साल के बच्चों में उम्र के अनुसार वज़न की जांच की गई;

3. गांव में हो रही मौतों की दर व कारणों की जानकारी इकट्ठी की गई।

सर्वे के पहले चरण में प्रशिक्षित स्वास्थ्य साथी महिलाओं द्वारा 25 टोलों (मोहल्लों) में 1663 बच्चों (1 से 5 साल तक) के कुपोषण की जांच बांह के मध्य भाग के नाप के आधार पर की गई। यदि 1 से 5 वर्ष के किसी बच्चे की बांह के मध्य भाग का नाप 13.5 से.मी. से कम है तो वह कुपोषित माना जाता है। जांच के बाद प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड प्रपत्र में दर्ज किया गया। ये स्वास्थ्य साथी महिलाएं अनपढ़ मगर प्रशिक्षित हैं और गांव में आम तौर पर होने वाली बीमारियों का इलाज करती हैं। इन्होंने सभी बच्चों के बारे में व्यवस्थित जानकारी इकट्ठी की। सर्वे के आधार पर पाटी ब्लॉक के इन गांवों में 1260 (75.7 प्रतिशत) बच्चे कुपोषित पाए गए।

इस सर्वे से प्राप्त जानकारी के आधार पर ज़्यादा गहराई से सर्वे करने की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए पास के बड़वानी ब्लॉक में भी सर्वे किया जाना तय हुआ। इस सर्वे में बेतरतीब ढंग से नमूना चुनकर (रेन्डम चुनाव) जानकारी इकट्ठी की गई। इस सर्वे के अंतर्गत पाटी ब्लॉक के 8 गांवों के 10 टोलों तथा बड़वानी के 8 गांवों के

बड़वानी ज़िले में कुपोषण सर्व के मुख्य निष्कर्ष

1. 84 प्रतिशत बच्चे कुपोषित।
2. 22 प्रतिशत बच्चे गम्भीर रूप से कुपोषित।
3. म.प्र. की औसत ग्रामीण मृत्यु दर (10.7 प्रति 1000) की तुलना में 14 प्रति 1000 वयस्क मृत्यु दर।
4. 132 में से 63 वयस्क कुपोषित व 15 गम्भीर रूप से कुपोषित

9 टोलों से 1 से 5 वर्ष के कुल 712 बच्चों का वज़न लिया गया, उनकी उम्र की जानकारी ली गई तथा उनके शरीर में आए बदलावों (कुपोषण के लक्षण जैसे बाल, चमड़ी, सूजन आदि) की विस्तार से जानकारी इकट्ठी की गई।

कुपोषण - वास्तविक स्थिति

इस सर्वे के अनुसार इन विकासखण्डों के कुल 84% बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से 22% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं (तालिका 1)।

इसके अतिरिक्त सर्वे के दूसरे चरण में चुने हुए गांवों में वयस्क व्यक्तियों में भी कुपोषण की जांच की गई। इस सर्वे के अंतर्गत 2 गांवों में 132 वयस्कों के वज़न व ऊंचाई नापे गए। बी.एम.आई. - बॉडी मास इंडेक्स - 18.5 से कम की माप के आधार पर 63 वयस्क कुपोषित और 15 गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए। बॉडी मास इंडेक्स का यह प्रमाण लगातार भूखे रहने की वजह से तीव्र कुपोषण दर्शाता है जो जानलेवा भी हो सकता है।

सर्वेक्षण के दूसरे चरण में पिछले एक वर्ष में तीन गांवों में हुई मौतों की जानकारी इकट्ठी की गई। इसके आधार पर पाया गया कि पिछले तीन महीनों में मृत्यु दर लगभग डेढ़ गुनी हो गई है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में औसत मृत्यु दर 10.7 प्रति 1000 व्यक्ति है, जबकि इन गांवों में यह 14 प्रति 1000 व्यक्ति से अधिक है।

इस बढ़ते कुपोषण के कारणों को देखा जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि क्या सूखा राहत कार्य व्यवस्थित ढंग से हुआ है? क्या लोगों को नियमित राशन मिल रहा है? क्या आंगनवाड़ी में बच्चों को नियमित रूप से पोषक आहार मिलता है? गांव में व्याप्त कुपोषण की स्थिति सरकार के आंगनवाड़ी कार्यक्रम की विफलता की कहानी कहता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं तथा मध्यप्रदेश में यह दर 55 प्रतिशत है। सरकार द्वारा इन आंकड़ों को गंभीरता से न लिए जाने के कारण कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यदि सूखे की इस स्थिति से तुरंत निबटने के प्रयास नहीं किए जाएंगे तो कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु दर बढ़ेगी और बेकाबू होती जाएगी।

राहत कार्य में लापरवाही के कारण लोगों को दो समय खाना नहीं मिल पा रहा है तथा भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान सरकार ने सूखा पीड़ित लोगों के लिए काम के बदले अनाज योजना इस साल के सितंबर माह तक चालू रखने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश को भी कम से कम नवम्बर माह तक राहत कार्य चालू रखना चाहिए। इस कार्य के दौरान न्यूनतम वेतन के बराबर अनाज या अनाज व पैसे दिए जाएं। इसके साथ-साथ सभी बच्चों को पोषक आहार देना सुनिश्चित किया जाए। सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति न पैदा हो, इसके प्रयास करने चाहिए। सरकार को तुरंत ही ऐसे सर्वे ज़िले के अन्य ब्लॉक तथा दूसरे सूखाग्रस्त ज़िलों में भी करवाने चाहिए। इस जानकारी के आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर उससे निपटने के प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। *(स्रोत फीचर्स)*

तालिका 1

कुपोषण का स्तर	मापदण्ड*	बच्चों की संख्या	प्रतिशत
सामान्य पोषित	80% से अधिक	114	16.0
थोड़ा या मध्यम कुपोषण	61-80%	442	62.1
गंभीर कुपोषण	60% से कम	156	21.1
कुल		712	100.0

*बच्चे का वज़न, उम्र के अनुसार अपेक्षित वज़न का कितना प्रतिशत है।